"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Haryana for the services of the financial year 1967-68 be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Haryana for the services of the financial year 1967-68, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 1, 2, 3, *the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI K. C. PANT: I beg to move:

"That the Bill be passed".

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

18.39 hrs.

INDIAN MISSIONS ABROAD*

श्री कामेश्वर सिंह (खगरिया) : अध्यक्ष महोदय, हमेशा से कहा जाता है कि जो भारतीय मिशन बाहर हैं उनमें मितव्ययिता लायी जायगी । परन्तु अभी तो जो इस मामले में हो रहा है उसको देखते हुए हंसी आती है । यह सारा हास्यास्पद है ।

[SHRI G. S. DHILLON *in the Chair*]

आज ही एक प्रश्न था । मैं उसकी ओर आप का ध्यान दिलाऊंगा—इंडियन एम्बैसी इन वाशिंगटन स्टार्ड क्वेश्चन नं० 723, उसके उत्तर में कहा गया है :

"The question of economy consistent with functional efficiency in the Indian Embassy in Washington as well as other Indian Missions abroad is constantly and continuously under Government's scrutiny and attention. All possible steps are taken to ensure that public funds are spent with the utmost care and to the maximum advantage."

सभापति महोदय, यह पहले भी कहा जा चुका है और आज भी कहा गया है—परन्तु मैं आपके सामने एक दो मिसालें रखता हूं—पिछले साल बजट सेशन के समय श्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि लन्दन का जो डिप्लोमेटिक सेट-अप है, उसमें जो स्टाफ़ है, उसमें आधी कमी की जा सकती है, वहां पर साधारणतया चार करोड़ रुपये का खर्चा होता है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा—पिछले बजट सेशन को साल भर हो चुका है, वहां के स्टाफ में कितनी कमी की गई है । जो बात मुरारजी भाई ने पिछले साल कही थी, वही बात जो इनके इंस्पैक्टर्स हैं, जो इण्डियन मिशन के स्टाफ़ को विज़िट करते हैं, उनका भी कहना था, परन्तु मुझे खेद है कि आज तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है ।

जो राजदूत यहां से जाते हैं, जिनको ये लोग अपायन्ट करते हैं, वे अपने आपको वहां पर हिन्दुस्तान का प्रेज़िडेन्ट ही समझते हैं तथा जनता के पैसे का दुरुपयोग, फिज़ूलखर्ची करते हैं, इसके एक दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं—वहां एक राजदूत गये, उनका कहना था कि उनके फर्नीचर को ठीक रखने के लिये

---

*Half-An-Hour Discussion.

[श्री कामेश्वर सिंह]

एयर-कन्डीशनर्ज का होना बहुत जरूरी है. . . . .

एक माननीय सदस्य : नाम बतलाइये ।

श्री कामेश्वर सिंह : नाम तो मैं नहीं बतलाऊंगा । लेकिन मेरे पास यह थर्ड लोक सभा की 47वीं रिपोर्ट है—इसमें लिखा है—

This is the 42nd Report of the PAC to the Third Lok Sabha.

"The Committee pointed out that electricity bills went up to as high as Rs. 9,000 a year because the air-conditioners were working for longer hours in order to protect the valuable furniture. The witness said that the Ambassador concerned wrote that the House was equipped with valuable furniture which would deteriorate if subjected to the vagaries of extreme climate in that place and it naturally required continuous air-cooling or heating of the premises which accounted for the rather high power and fuel charges."

चेयरमैन साहब, इस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं कि कितनी इकानमी वहां पर की जा रही है । जब एक कमेटी बैठती है और उसकी रिपोर्ट आती है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसका क्या असर होता है ? पिछले साल मोरारजी भाई ने कहा कि स्टाफ में कमी हो सकती है, 50 परसेन्ट स्टाफ़ घटाया जा सकता है, आपके इंस्पैक्टर्स ने भी उसी किस्म की रिपोर्ट दी, तो उसके बाद चार करोड़ रुपये के खर्च में आपने कितना खर्च घटाया । यह एक्जाम्पल मैंने इसलिये दी है कि जितने भी मंत्री उस तरफ़ बैठते हैं या जितने भी हमारे दोस्त उधर हैं, वे कहते हैं कि हम लोग गलत, उलजुलूल और फिजूल की बातें करते हैं, परन्तु हमारे कहने की सत्यता इन रिपोर्टों से जाहिर होती है ।

मैं आपके सामने एक दूसरा उदाहरण रखता हूं—हमारे जो राजदूत बाहर जाते हैं, वे कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं—उसका नमूना देखिये । यह बात 1961 की है, जब लाओस कमीशन रिकन्वीन हुआ था । जो हाई कमिश्नर उस समय आस्ट्रेलिया में था, उन्हीं को वहां जाना था, ऐसी जगहों पर जाने के बाद उनको बहुत सारे एलाउन्सेज मिलते हैं । बड़े लोग हैं, खूब एलाउन्सेज लेते रहे, उनकी पत्नी के लिये आदेश मिला था कि वह आस्ट्रेलिया में रहें, लेकिन वे उनका भी एलाउन्स लेते रहे, जब मिनिस्ट्री ने देखा और उनसे कहा कि आपने ज्यादा एलाउन्सेज ड्रा किये हैं, इसलिये आप इस रकम को लौटाइये । बजाय इसके कि वह उस रकम को लौटाते, उन्होंने क्या जवाब दिया—उसका नमूना देखिये—

"The witness further added that the Ministry had asked the Ambassador's family in August, 1965. . . .".

यह बहुत दिन पहले की बात नहीं है, 1965 की बात है—

". . . . to refund the entire amount of Rs. 4,405 drawn by him and to give the details of the inescapable expenditure incurred during his absence."

बहुत ज्यादा लिखा-पढ़ी के बाद भी उन्होंने उस रकम को नहीं लौटाया, अन्त में क्या हुआ कि वह रिटायर भी हो गये और जहां तक मुझे मालूम है, वह पैसा वैसे ही चला गया । यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, जिसको हाई कमिश्नर साहब दे नहीं सकते थे—परन्तु इस प्रकार का उदाहरण बहुत खराब बात है । अगर बड़े आफिसर्ज इस तरह से करेंगे, तो इसका छोटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा । इस तरह की चीजों से ही हमारे काम करने वालों के अन्दर इन्एफिशियेन्सीज़ पैदा होती हैं, इकानामी हो नहीं पाती है और हमारी गवर्नमेन्ट की जो पालिसीज हैं, उनको वे ठीक तरह से बाहर रख नहीं पाते । इसलिये इस में सारा दोष सरकार का है । जितने भी मिशन्ज बाहर काम करते हैं, उनके लिये

विदेश विभाग जिम्मेदार है, वह ऐसे लापरवाह लोगों को बाहर भेजता है, जो विदेशों में जाकर भारत की जो विदेश नीति है, उसको वहां के लोगों के सामने ठीक प्रकार से रख नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है ? जो बाहर जाता है उसको देश की नीतियों में विश्वास नहीं होना है, और जब किसी को अपनी ही नीतियों में विश्वास नहीं है तो वह उसको दूसरों के सामने कैसे पेश कर सकेगा। जैसे मैथमैटिक्स में दो को दो से गुणा करें तो उत्तर चार आयेगा, यदि इनको जोड़ें तो भी चार आयेगा—तो विभिन्न परिस्थितियों को विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार से रखने और समझाने की ज़रूरत होती है, जिसमें ये लोग बिलकुल फेल करते हैं, कभी ठीक से समझा नहीं पाते हैं। कांग्रेस के जितने छांटे हुए आदमी हैं, जिनको जनता छांट देती है, जिनको अपनी कांस्टीचूएन्सी में वोट नहीं मिलता है, वे जब हार जाते हैं तो राजदूत बना दिये जाते हैं। आज कल एक दूसरी परिपाटी भी शुरू हो गई है, जितने जैनरल्ज़ रिटायर होते हैं, चाहे वे काबिल हों या न हों, उनको राजदूत या हाई कमिश्नर बनाकर भेज दिया जाता है। शायद सरकार ने यह परिपाटी जान-बूझ कर चलाई है कि जितने जैनरल्ज़ रिटायर हों उनको बाहर भेज दो, जिससे कि गवर्नमेन्ट को कोई डर न रहे, कहीं कोई मिलिट्री रूल न हो जाय, उससे सेफटी हो जायगी। अगर जैनरल्ज़ राजदूत बन कर चले जायेंगे तो सरकार का सारा मतलब पूरा हो जायगा। सरकार का मतलब पूरा होना चाहिये, चाहे पब्लिक का ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो, चाहे जितनी इनएफिशियेन्सी बढ़े, चाहे जितनी लागर्जी, लापरवाही बढ़े—इन सारी बातों से तो यही जाहिर होता है।

लन्दन में इस वक्त जो स्टाफ है, उनमें 930 आदमी हैं, जिनमें से दो-तिहाई लन्दन में ही भरती किये गये हैं, उन लोगों को विदेशी मुद्रा में स्टर्लिंग में पे किया जाता है और यह स्टाफ़ आज तक वहां पर है। भारतीय मिशन के अलावा वहां पर सप्लाई मिशन है, डिफेन्स का सेट-अप वहां पर है, कहीं भी किसी तरह की कटौती नहीं की जा रही है। जब भी कटौती की बात किसी मिनिस्ट्री में आती है तो कहते हैं कि भारत के लिये वहां पर स्टाफ़ रखना बहुत आवश्यक है। आज जब कि हम डिफेन्स का काफ़ी सामान खुद तैयार कर रहे हैं, रूस से ले रहे हैं, दूसरे देशों से ले रहे हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है कि लन्दन में स्टाफ होना चाहिये—इस को घटाने का कोई चारा नज़र नहीं आता है।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इनसे हर बात का जवाब चाहता हूं। मैं यह जवाब नहीं सुनना चाहता हूं कि ये बातें ऐसी हैं, जिनको हम बता नहीं सकते हैं, या ये हमारे इन्टरनल मामले हैं या हमारे पास इनके बारे में इन्टरनल रिपोर्टस हैं। चेयरमैन साहब, हमने उन रिपोर्टस् की बातों को बहुत सुना है, साल भर से सुनते-सुनते हम थक गये हैं, हालांकि मैं थकनेवाला आदमी नहीं हूं। अब मैं आपके सामने कुछ और मामले भी रखूंगा—जिस प्रश्न पर आज मैंने यह डिस्कशन उठाया है, उसके जवाब के आखिर में कहा है—

"The missions are exhorted to effect economy in expenditure on telegrams, travelling allowances, furniture and other valuable items of expenditure. It is expected that these measures will result in restricting the expenditure to an irreducible minimum. An economy of Rs. 36.60 lakhs approximately is expected to be realised by the measures already taken."

तमाम चीजों पर सोचने के बाद साल भर में—कहते हैं—36.60 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं। चाहे फाइनेन्स मिनिस्टर कुछ भी कहे, उसका कुछ भी असर नहीं है। इस क्वेश्चन के आन्सर से डाइरेक्टली कनेक्टेड एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित

[श्री कामेश्वर सिंह]

करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि टेलीग्राम और अन्य चीजों में 36 लाख की कटौती होगी लेकिन मारके की चीज यह है कि टेलेक्स सिस्टम की स्थापना कुछ ही मिशनस के साथ हो सकी है। ज्यादातर इम्पार्टेन्ट मिशन्स ऐसे हैं जिनके साथ हमारा टेलेक्स का डाइरेक्ट रिलेशन नहीं है। नतीजा यह होता है कि जो बातें बाहर की होती हैं उनके यहां तक पहुंचने में देरी होती है और उनको प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। सेक्रेटेरियट या जो डिसीजन मेकिंग मशीनरी है उस तक बातें बहुत देर में पहुंचती हैं। और जो बातें हम सोचते हैं वह भी बाहर बहुत देर में पहुंचती हैं। टेलेक्स सिस्टम एक्सपेडिशस है और एकोनामिक भी है। 27 नवम्बर के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने यदि कहा होता कि कोशिश की जाएगी, अधिक से अधिक भारतीय मिशनों के साथ टेलेक्स सिस्टम कम समय में स्थापित किया जायगा तब भी संतोष होता लेकिन संतोष की तो कोई बात ही नहीं है।

अब में आपका ध्यान दूसरी ओर खींचता हूं। आज ही के उत्तर में कहा गया है कि इंडियन इम्बैसी (अमरीका) में 1,51,13,750 रु० खर्च होता है। खुशकिस्मती से आज ही यह जवाब आया और आज ही यह प्रश्न भी आया है। अमरीका में इंडियन मिशन अपने अधिकारियों को जो होटल एलाउन्स वगैरह देता है उसके मुकाबले में कनाडा में कुछ भी खर्चा नहीं है। मैं इस तरफ खास तौर से मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह जवाब देंगे। कनाडा में इसलिए एलाउन्सेज पर कम खर्चा है—मैं नयी पोस्टिंग के सम्बन्ध में कह रहा हूं—कि वहां एकोमोडेशन मिल जाती है और वाशिंगटन में जगह नहीं मिलती है। तो वहां पर आप मकानों को क्यों नहीं बनवाते हैं या खरीदते हैं? क्या अधिक से अधिक किराया देना ही हमारा काम है? हमारे राजदूत जो कि पहले मिनिस्टर रह चुके होते हैं या अन्य पदों पर रह चुके होते हैं, वे बूढ़े और पुराने लोग अपना रेजिडेन्स खरीदने में ही इन्टेरेस्ट लेते हैं बनिस्बत इसके कि मिशन के लिए एक अच्छी सी बिल्डिंग हो जाए। यही कारण है कि हमारे मिशन्स में एफीसिएन्सी नहीं बढ़ रही है। जो रेजिडेन्स खरीदे जाते हैं वह भी बराबर बदलते रहते हैं। इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं।

आजादी प्राप्त किए 20 साल बीत गए लेकिन आज भी हिन्दुस्तान पर काला धब्बा है। लंदन में जो भारतीय राजदूत का निवास-स्थान है उस पर अभी तक क्राउन है। छागला साहब ने कुछ समय पहले एक प्रश्न के उत्तर में कहा था जिसको आज भी पढ़कर मुझे ताज्जुब होता है और आपको भी शायद ताज्जुब होगा :

'The ambassador is considering the proposal and it involves a major operation.'

मेरी समझ में नहीं आता कि जब आपका मकान है, उसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन है तो उसको निकाल देने में कौन सा मेजर आपरेशन हो जाता है। कच्छ हो या कोई और जगह, वहां तो मेजर आपरेशन होता नहीं, लेकिन यहां पर माइनर आपरेशन को भी छागला साहब ने मेजर आपरेशन बता दिया।

सभापति महोदय : यह हाफ एन आवर डिस्कशन है। मिनिस्टर साहब को जवाब देना है और क्वैश्चन्स भी पूछने हैं।

श्री कामेश्वर सिंह : वैसे तो यह 24 घंटे में भी समाप्त नहीं होने वाला है लेकिन मैं अगले 10 मिनट में ही खत्म कर दूंगा।

तो छागला साहब ने उसको मेजर आपरेशन बता दिया। अगर अभी भी उनको ब्रिटिश शासन की गुलामी करनी है तो उनको मुबारक हो लेकिन जनता इसको पसन्द नहीं करती है।

अब मैं एक प्रश्न और उठाना चाहता हूं। बाहर हमारे जो मिशन्स हैं वहां पर जो पब्लिसिटी करने वाले लोग हैं वे अभी तक टेम्पोरेरी हैं। इंफार्मेशन आफिसर्स की कोई पूछ नहीं है। नतीजा यह होता है कि वे आधे दिल से काम करते हैं, हाफ हार्टेडली काम करते हैं। आप कहेंगे कि पब्लिसिटी आफिसर्स का यहां पर क्या सम्बन्ध है, लेकिन उन पर भी रुपया खर्च होता है। यदि वह काम ठीक से नहीं होता तो अवश्य एकोनामी में कोई खलल है। पिल्लई कमीशन ने भी रिपोर्ट दी है कि उनको एबजार्व कर लेना चाहिए लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

एक बात में यह कहना चाहता हूं कि जो बाहर से लोगों को ऊंचे पद पर लिया जाता है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, इसके कारण हर तरफ डिसकन्टेन्ट बढ़ता है। इसके अलावा पिछले 20 वर्षों में शायद सरकार अभी तक यह तय नहीं कर पायी है कि एक फारेन सर्विस के आदमी को, जिसको अन्दाजन 30 साल नौकरी करनी होती है, कितने दिन देश में रहना है और कितने दिन बाहर रहना है। इसी वजह से लोगों में असंतोष फैलता है। बहुत से लोग हैं, मंत्रियों के पिट्ठू; जो कि आज भी दिल्ली में 12-12 साल से हैं और बहुत से लोग जो बाहर हैं, वे बाहर ही हैं, न वे आते हैं और न जाते हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं विदेश विभाग में जो कि दस-दस साल से यहां अड़े हुए हैं। शायद एक साहब तो 12 साल से भी हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा असंतोप है।

इसके अलावा आज कल इन्टरनेशनल डिप्लोमैसी जो है, कूटनीतिक कार्यों के अलावा, कार्माशियल ट्रेड और एकोनामिक कार्य भी काफी बढ़ गए हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हमारे कार्माशियल विभाग में जो लोग हैं उनके एप्वाइन्टमेन्ट्स का क्या तरीका है, क्या क्राइटेरिया है ? कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। मैं गम्भीरतापूर्वक कहना चाहता हूं कि कामर्स और ट्रेड से सम्बन्धित जो लोग बाहर मिशन्स में हैं उनको अर्थशास्त्र का ज्ञान भी नहीं है। पब्लिसिटी, प्रेस वाले या पब्लिक रिलेशन्स आफिसर जो हैं उनको किस बात के लिए भरती किया जाता है ? मैं नहीं समझ पाता कि बाहर हमारे मिशन्स की क्या हालत हो रही है। इंडिया जो कि दुनिया में सबसे बड़ा डिमोक्रैटिक कन्ट्री है उसके मिशन्स की आज यह दशा हो रही है। इसका कारण क्या है ? इसका कारण है हमारी सरकार की कमजोरी। वह बाहर कन्ट्रोल नहीं कर पाती है। वह ऐसे लोगों को एम्बेसेडर बनाती है जो कि डिप्लोमैसी से बहुत दूर रहते हैं, उनको कोई भी अनुभव नहीं रहता है। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारे यंग आफिसर्स में असंतोष फैलता है। पिल्लई कमीशन ने भी कहा है कि जो प्रमोशन्स हों उनमें सीनियारिटी के अलावा मेरिट को भी देखना चाहिए परन्तु उसकी कोई परवाह नहीं की जाती है। यंग आफिसर्स को दवाया जाता है। दवाने का नतीजा यह होता है कि उनमें असंतोष फैलता है और आप जो पैसा भी खर्च करते हैं वह भी कारगर नहीं होता है।

अन्त में मैं जानना चाहूंगा कि जो बातें मैंने कही हैं उनको दूर करने के लिए और भारतीय मिशन जो बाहर हैं उनमें मितव्ययिता लाने के लिए—श्री मोरारजी देसाई के पिछले साल बजट सेशन में यह कहने के बाद कि लंदन का स्टाफ आधा किया जा सकता है—क्या कदम आज तक उठाए गए हैं तथा जो प्रोमोशन्स आफिसर्स के होते हैं सीनियारीटी की बेसिस पर, न कि मेरिट पर, उसके विषय में भी मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा।

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi) : Sir, in asking a question, I do not wish to suggest that I would paint the picture entirely black, but I think the minister

[Shri M. L. Sondhi]

would be less than fair to himself if he does not take into account the apprehension in the minds of many members of this House that there is a great need for fresh and new thinking so that a better arrangement may exist in the ministry. Coming to the question of foreign service, may I ask the minister whether he has ever contemplated himself the precise relationship from the point of view of the efficient distribution of personnel, an emphasis of rationality imposed in people so as to get better results rather than merely a focus on allowances and perquisites of living ? In this connection, the Senior Establishment Board seems to be evolving a policy which to the outsider seems to reflect either gross mismanagement or some sort of carelessness about what is the proper criterion in this respect. For example, there is the criterion that postings should not be announced more than six months in advance. I know of a posting to Washington announced a year in advance. A recent posting to Birmingham I am told was the subject of some review when the matter was raised in Parliament and high officials and senior officials felt that the prestige of the Ministry was involved and, therefore, since it was a prestige issue it was decided that the posting must be maintained.

19 hrs.

I am also told that certain stations are regarded as very good stations for posting not from the political point of view but from allowances point of view. I am told, for example, that Manila is a place where everyone wants to go. I am also informed that a certain post of P.A. in Manila was upgraded to that of P.S. in order to allow a certain type of posting. I am not suggesting that we go into these matters with some feeling that we have discovered a scandal. I think in most cases if the Minister has courage, determination and the sense of purpose—it has been done by people in other Governments; for example the Plowdon Committee in England, the reform in the United States, the reform in Yugoslavia or the reform in Israel—we can get here similar standards in which efficiency and achievement would be the motivations amongst members of the foreign service be they top officials or or be they people lower down. But if the Ministry is going to make every matter a prestige case, even doing wrong things being regarded as prestige issues, then I think we do not need a democratic system and perhaps a military take-over would get us better diplomacy. But we are committed to democracy and we in the Jan Sangh are willing to sacrifice our all for the sake of democracy. Therefore, my question in this. What are the rules which are available for the selection of foreign service inspectors ? Are these people who are mediocre and who have nothing else to do sent for foreign service inspection or are our foreign service inspectors the best, the pick of your service, who have the requisite authority even to challenge the decisions of the Senior Establishment Board ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : Mr. Chairman, Sir, I have listened to the speech of the hon. Member very carefully and I find that the scope of the discussion has been greatly enlarged and many things have been brought into the discussion which I think could better be left for a suitable occasion when a proper debate will take place on the foreign affairs. Many points have been raised during the discussion and it may not be possible for me to cover all of them within the short time at my disposal. I will try to reply to as many points as possible in the short time that has been given to me.

With regard to the question of inefficiency and economy which the hon. mover of the discussion has raised, this question of inefficiency in our foreign missions is a subject which is constantly under our watch and we are watching it very carefully. There is constant dialogue between the Missions and the Ministry by correspondence and we see that all Missions abroad function as efficiently as possible. It is possible that out of a number of Missions that we have abroad, a few here and there may not be functioning properly. If the hon.

Member had actually pointed out those, that would have been understandable, but to make a sweeping allegation that all Missions are not functioning properly and that inefficiency is on the increase day by day is a contention which I am not prepared to accept because, as I said earlier on......

श्री कामेश्वर सिंह : मैंने लंदन के मिशन के बारे में खास तौर से कहा है। मंत्री महोदय लंदन के मिशन के बारे में जवाब दें।

SHRI M. L. SONDHI : London is worse than our Secretariat.

SHRI SURENDRA PAL SINGH : The hon. Member mentioned something about our Deputy Prime Minister having said that the staff in London can be reduced by half. I do not know what exactly he said about that, but I can assure the hon. Members that every effort is being made by us to see that superfluous staff is reduced as early as possible. I may give this information to the Members that whereas in 1966 there were 960 posts in London, these posts were reduced by 110 and at present there are only 850 people in the High Commission staff and the total reduction in expenditure on our High Commission in London, the savings, came to about Rs. 24 lakhs as a result of reduction in strength. I am giving the savings as a result of reduction in staff. Anyway, this is a continuous process and we keep on doing it again and again. We do feel that there is some justification for further reduction and this matter is being looked into. The Foreign Service Inspectors have also given their recommendations which are being considered.

I have also got figures here about the total expenditure on our Missions abroad which will also indicate what we were able to economise and save. In 1967-68 the total expenditure on our Missions abroad was Rs. 983 lakhs and the economy effected over the same period was of the order of Rs. 43.82 lakhs.

SHRI KAMESHWAR SINGH : Not even 5 per cent.

SHRI SURENDRA PAL SINGH : Then, the hon. Member referred to some of our envoys not being competent enough to interpret the Government's policy abroad and to project the image of India. I am afraid this is a very sweeping remark which he has made. They have acquitted themselves well.

SHRI M. L. SONDHI : Whenever any crisis takes place in any country they are never present on the spot. I can give at least five examples.

SHRI SURENDRA PAL SINGH : Then, do we take it they knew about the impending crisis and then left the place? It is a matter of coincidence that in one or two places when some crisis or *coup d'etat* took place our envoy was not there. It is not as if be anticipated it and then wept away from there. It is just a matter of chance. It is not quite correct to say that all our envoys are not really competent people and that they are not able to interpret the policies of the Government of India properly. It is quite possible that in a big organisation of this nature where there are hundreds of people working abroad there may be a few black sheep here and there, which we have in every fold. But to say that all of them are incompetent is not quite correct. Any way, this matter too is being looked into and we are very watchful and whenever any complaint comes from outside that our envoys are not up to the mark, we take necessary corrective actions.

A question was raised about the inscription on India House, London. I have just now received information that the inscription on India House is being changed, so also the inscription and the entire facade. The entire facade is being changed, so also the inscription and the Crown is being removed.

श्री कामेश्वर सिंह : यह कब तक हो जायगा ?

SHRI SURENDRA PAL SINGH : It is very difficult to remove them. I hope it will be done very shortly. I cannot give any time.

[Shri Surendra Pal Singh]

Reference was also made to Information Officers who are working in our missions abroad and it was said that they are not being made permanent and are not being absorbed in the Foreign Service. The position is not as the hon. Member has made out. The correct position is somewhat like this, namely, that ISI officers are also eligible for being taken into regular service as Foreign Service officers. So far five ISI officers have been taken into the regular IFS cadre. They are not on a temporary basis; they are permanent officers. Gradually they are being taken into the Foreign Service also.

As regards telex facilities with our missions abroad, we already have telex facilities with about 24 of our missions abroad and for future the policy that when we find on making an assessment that the expenditure incurred on other communications is more than the telex, we try and provide telex facilities as early as possible. But it is a question of comparative cost and expenditure.

Then, I was asked to give figures of some of our officers in the Foreign Service who have been at headquarters for more than 5 or 10 years. I may inform the hon. Member that there are only two officers at headquarters who have been here for a period of more than ten years.

श्री कामेश्वर सिंह : कम से कम दो हैं यह आपने माना था। मुझे बहुत खुशी है इस के लिये।

SHRI SURENDRA PAL SINGH. But the number is not very large. I think, I have covered most of the points.

श्री कामेश्वर सिंह : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इंडियन मिशन्स में कितने फारेनर्स इंटरप्रेटर्स और ट्रांस्लेटर्स का कार्य कर रहे हैं, इसमें कितना फारेन एक्स्चेंज खर्च होता है और कब तक वह इंडियन इंटरप्रेटर्स और ट्रांस्लेटर्स में बदल जायेंगे और आज जो फारेन एक्स्चेन्ज का ड्रेन हो रहा है उसको बचा सकेंगे ? यह बहुत बड़ा एकानामी का सवाल है।

SHRI SURENDRA PAL SINGH: It will not be possible for me to give the information that the hon. Member requires now but this could be given to him later on.

As regards the question that the hon. Member, Shri Sondhi, has raised as to whether our foreign service inspectors are competent people and the criteria on the basis of which they are selected, I can just say that our foreign service inspectors are very competent people. They are senior officers with a great deal of experience and we see to it that the best possible officers are chosen for this job. Those who are already working in this category are doing extremely good work and we need have no apprehension that we are getting mediocre people who will not be doing their work properly. It is not so.

SHRI M. L. SONDHI: My point was not this. My point is a general point and it is not intended in any malicious sense. In most foreign services it happens that since the best minds are working in day-to-day diplomacy, some people who are not accommodated tend to gravitate towards the foreign service inspectorate. What steps are you taking to prevent such a disfunctional aspect of bureaucracy? It is something which is bound to be there unless you take some steps to the contrary. That is why I asked you as a test case as to whether these foreign service inspectors have a right to challenge the decision of the senior establishment board because it would bring it into the open and it will be the index of their real strength in the department.

SHRI SURENDRA PAL SINGH: All I can say is that the people we have selected are competent and experienced people. They are doing a good job. They do go abroad on inspection trips and submit their reports which are given careful attention.

SHRI M. L. SONDHI: My point was with regard to efficient distribution of personnel. There are two or three things which the foreign service inspectors do. They make recommendations about allowances, find out about the security aspect of the mission and also

make recommendations about the distribution of personnel. So, I would like you to answer the question whether there are recommendations about the distribution of personnel. I even quoted examples of Manila and Birmingham and other places. What is the value of their reports? You are not disclosing their reports to Parliament though Parliament pays for their going abroad; after all it is the money sanctioned here which enables them to go abroad. So what is the usefulness of their reports and how much of it is implemented, because inside the Ministry there is bound to be pressure against their implementation as they will be challenging the decisions of certain other people? It is not the question of competence but of the prestige and authority which these foreign service inspectors must possess.

SHRI SURENDRA PAL SINGH: We do give the utmost importance to the recommendations of the Foreign Inspectors' Report. It is not possible to disclose the nature of the Report. But we do attach a great deal of importance to it and there is no resistance as such. If they have made any good recommendations, we try to implement those recommendations and we give the utmost importance to the recommendations.

MR. CHAIRMAN: Now the House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 A.M.

19.16 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 21, 1968/*Chaitra* 1, 1890 (*Saka*)

L/19LSS(CP)/68—1010—4-10-68—GIPF.